alpex
POWER FOREVER

ALPEX SOLAR LTD.
(Formerly known as Alpex Solar Pvt. Ltd.)
I 25-26, Site-V, Surajpur Ind. Area,
Kasna, Greater Noida,
(U P) - 201306 (India)
Tel. No.: +91 120 2341146
E-mail : info@alpex.in

Date: May 22, 2026

To
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, Plot No. C-1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai– 400051

Symbol: ALPEXSOLAR, ISIN: INE0R4701017

Sub: Newspaper Publication – Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed extracts of the newspaper advertisement published on May 22, 2026, in the following newspapers:

- The Economic Times - English Newspaper (All India Edition)
- Swatantra Chetna - Hindi Newspaper (Regional Edition)

The Financial Results published in the above newspapers contains a 'Quick Response (QR) code' and details of the webpage where complete Financial Results of the Company are available.

The advertisement pertains to the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2026, as approved by the Board of Directors of the Company at its Meeting held on Thursday, May 21, 2026.

You are requested to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Alpex Solar Limited

SAKSHI TOMAR
Digitally signed by SAKSHI TOMAR
Date: 2026.05.22 12:20:20 +05'30'

Sakshi Tomar
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.- A48936

1986-2026 41 वां वर्ष स्वर्ण जयंती की ओर अग्रसर

राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र

स्वतंत्र चेतना

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड व नई दिल्ली से प्रकाशित

नई दिल्ली
वर्ष 12,अंक 264
शुक्रवार 22 मई ,2026
पृष्ठ 12 ₹2.00

www.swatantrachetnanews.com

गोरखपुर , लखनऊ , प्रयागराज , कानपुर , नई दिल्ली , हरिद्वार , वाराणसी ,आजमगढ़ व अयोध्या से प्रकाशित

बॉबी देओल की फिल्म बंदर का ट्रेलर रिलीज

घुसपैठियों को कोर्ट में पेश करने के बजाय सीधे बीएसएफ को सौंपे : शुभेन्दु

दिल्ली में नए राशन कार्ड बनने शुरु,7.72 लाख लोगों को मिलेगा लाभ : रेखा

अब 1.20 लाख आय वाले भी बनवा सकेंगे राशन कार्ड,7.71 लाख अपात्र नाम हटे

स्वतंत्र चेतना

नयी दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को घोषणा की कि लगभग 13 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में बड़े पैमानो पर नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया 15 मई से दोबारा शुरू कर दी गई है।

श्रीमती गुप्ता ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों से आवेदन करने की अपील करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अंत्योदय संकल्प को आधार बनाकर यह सुनिश्चित कर रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि 15 मई 2026 से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से नए राशन कार्ड और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा चुके है। इसके अतिरिक्त पहले से जमा किए गए पुराने आवेदन पत्रों को आवेदकों के लॉगिन प्रोफाइल पर वापस भेजा गया है। आवेदक वर्तमान फैमिली इनकम सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ इन्हें दोबारा अपडेट कर जमा कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद राशन वितरण व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराया, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आईं। जांच में कुल 7,71,384 अपात्र और फर्जी लाभार्थी पाए गए। इनमें 6,46,123 लोग निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले थे इसलिए राशन पाने के पात्र नहीं थे। इसके अलावा 95,682 ऐसे लाभार्थी मिले जिन्होंने पिछले एक वर्ष से राशन लिया ही नहीं था। वहीं, 6,185 मामलों में मृत व्यक्तियों के नाम राशन रिकॉर्ड में दर्ज थे और 23,394 लाभार्थी ऐसे पाए गए जो एक से अधिक स्थानों से राशन का लाभ ले रहे थे।

उन्होंने कहा कि इन सभी अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाने के बाद बड़ी संख्या में स्थान खाली हुए हैं। इससे करीब 7.72 लाख नए पात्र लोगों को राशन कार्ड जारी करने का रास्ता साफ हुआ है। फिलहाल नए राशन कार्ड के लिए 3,72,367 आवेदन और राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए 99,501 आवेदन लंबित हैं। चूंकि समय के साथ लोगों के निवास, आय और पात्रता की स्थिति बदल सकती है, इसलिए सभी आवेदकों को मौजूदा नियमों और नई पात्रता शर्तों के अनुसार फिर से आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2026 लागू कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया है। इसके तहत राशन वितरण व्यवस्था में बड़े स्तर पर डिजिटल सुधार किए गए हैं। राशन दुकानों पर पारंपरिक वजन मशीनों की जगह ई-वेइंग मशीनें लगाई जा रही हैं और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। अब बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के राशन वितरण नहीं होगा, जिससे कम राशन मिलने और गड़बड़ियों की शिकायतों पर रोक लगेगी।

उन्होंने बताया कि नए राशन कार्ड के लिए आवेदन, नाम जोड़ने या हटाने समेत राशन कार्ड से जुड़ी सभी सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई हैं। नागरिक घर बैठे या अपने नजदीकी सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से राशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, तकनीक-संचालित और लाभार्थी-केंद्रित बनेगी तथा पात्र लोगों तक राशन का लाभ सही तरीके से पहुंच सकेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले परिवार की आय संबंधी जानकारी केवल स्व-घोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन) के आधार पर स्वीकार की जाती थी। इसके कारण कई बार अपात्र लोगों को भी राशन का लाभ मिल जाता था, जबकि वास्तविक जरूरतमंद लोग इससे वंचित रह जाते थे। अब नयी व्यवस्था के तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय परिवारों को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, नवीनतम आय प्रमाण पत्र और परिवार के सभी सदस्यों का आधार विवरण जमा करना होगा।

ईरान जंग पर ट्रंप-नेतन्याहू में टकराव,तनावपूर्ण में हुयी बात

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमले जारी रहें, जबकि ट्रम्प फिलहाल बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि नेतन्याहू ने ट्रम्प से कहा कि ईरान पर प्रस्तावित हमले रोकना गलती है और सैन्य कार्रवाई जारी रहनी चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक, ट्रम्प ने रविवार को नेतन्याहू को बताया था कि अमेरिका ईरान पर नए टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहा है।

अमेरिका डील चाहता है,इजराइल बोला हमला नहीं रुकना चाहिए,ऐसा किया तो गलती होगी

इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्लेजहैमर नाम दिया जाना था। लेकिन करीब 24 घंटे बाद ट्रम्प ने घोषणा कर दी कि मंगलवार के लिए तय हमलों को फिलहाल रोक दिया गया है। ट्रम्प ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों की अपील पर यह फैसला लिया गया।

यात्रा के दौरान सतर्क रहें यात्री:वैष्णव

किसी भी संदिग्ध गतिबिधियों के बारे में हेल्पलाइन नं.139 पर सूचना दें,रेलमंत्री ने कहा आधुनिक तकनीक का उपयोग करके फील्ड से खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया में किया जा रहा है सुधार

स्वतंत्र चेतना

नयी दिल्ली। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों या उसमें शामिल व्यक्तियों के बारे में सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 सूचना देने की अपील की है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को यहां हाल में घटित हुई घटनाओं को लेकर यहां अधिकारियों के साथ यात्रियों और रेल सम्पत्ति की सुरक्षा को लेकर उठाये जा रहे कदमों को लेकर उच्च-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। इस दौरान ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से जमीनी स्तर से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त तकनीक-आधारित सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, पूरे रेल नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज का विस्तार करने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा विभिन्न क्षेत्रीय मंडलों के बीच परिचालन सुरक्षा समन्वय को बेहतर बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया।

बैठक में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, कैमरों के स्पेसिफिकेशन को उन्नत करने और कृत्रिम बुद्धिमता-आधारित निगरानी और निगरानी प्रणाली लगाने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा रेलवे नेटवर्क पर ज्यादा असरदार सुरक्षा प्रबंधन के लिए आरपीएफ और सरकारी रेलवे पुलिस के बीच जानकारी शेयर करने के तरीकों को बेहतर बनाकर तालमेल को मजबूत करने पर भी खास ध्यान दिया गया।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने श्री वैष्णव को बताया कि रेलवे ट्रेनों, यात्रियों, स्टेशन परिसर और अपने विशाल रेल नेटवर्क की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), ड्रोन, सीसीटीवी जैसे नवीनतम तकनीकी उपकरणों का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहा है। यह कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है और इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के बीट स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

इस बैठक में श्री वैष्णव के अलावा रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू के साथ-साथ रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार और देश भर से आए क्षेत्रीय अधिकारी शामिल हुए।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में घटित हुई घटनाओं (जिनमें आग लगने की कुछ हाल की घटनाएं भी शामिल हैं) की शुरूआती जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। भारतीय रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और आरपीएफ इनकी जांच कर रहा है। कई मामलों में, रेलवे द्वारा की गयी त्वरित और सक्रिय कार्रवाई की बदौलत बड़ी दुर्घटनाओं को टालने में सफलता मिली है।

रेलवे ने गुरुवार को जारी विज्ञप्ति में कहा है कि बैठक में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए खुफिया प्रणालियों को मजबूत करने और सूचनाओं पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए तकनीक का उपयोग करने के अलावा यात्रियों को भी इस बात के लिए और अधिक प्रोत्साहित करेगा कि वे अपनी यात्रा के दौरान और स्टेशन परिसर में प्रतीक्षा करते समय असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों में सक्रिय रूप से सहयोग करें।रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहें।

इबोला वायरस को लेकर हवाई अड्डे अलर्ट,निर्देश जारी

स्वतंत्र चेतनानई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इबोला वायरस को लेकर हवाई अड्डों पर विशेष एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों में यदि इबोला से जुड़े लक्षण दिखाई दें तो तुरंत कार्रवाई की जाए।केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं (डीजीएचएस) ने गुरुवार को यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जारी परामर्श में यात्रियों को स्पष्ट रूप से बताया है कि उच्च जोखिम वाले देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले या वहां से होकर गुजरने वाले यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।

दिल्ली में गर्मी का 14 साल का रिकार्ड टूटा,दिन ही नहीं रात में भी सितम

स्वतंत्र चेतना

नई दिल्ली। दिल्ली में मई महीने की अब तक की सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जब न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार यह पिछले लगभग 14 वर्षों में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान है। इससे पहले 26 मई 2012 को न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सफदरजंग और लोधी रोड सहित कई स्टेशनों पर रात में गर्म मौसम की स्थिति रही।

गर्म रात तब घोषित की जाती है जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है।

आईपीएल में आज

हैदराबाद बनाम बेंगलुरु
स्थान-हैदराबाद
समय-शाम 7.30 बजे

पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा बरहान मारा गया

स्वतंत्र चेतना

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान पीओके के मुजफ्फराबाद में अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में मारा गया। उसे कई गोलियां लगीं। हमले के बाद उसके साथियों ने उसे तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल का हमजा बुरहान भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-बद्र से जुड़ा था। उसका पूरा नाम अरजुमंद गुलजार डार था, जिसे उसके सर्किल में ह्यडॉक्टरह्न के नाम से भी जाना जाता था।

न्याय प्रणाली को आरोपितों से ज्यादा पीड़ितों को प्राथमिकता देनी चाहिए: सुप्रीमकोर्ट

कहा हर धोखाधड़ी का मामला अलग होता है,पीड़ितों के अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है

स्वतंत्र चेतना

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि न्याय प्रणाली को आरोपितों से ज्यादा पीड़ितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 49 करोड़ रुपये के फजीर्वाड़े के मामले में 53 एफआईआर को एक साथ करने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की।

कोर्ट ने कहा कि हर धोखाधड़ी का मामला अलग होता है और पीड़ितों के अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने पूछा कि ऐसे अपराधों के पीड़ितों के अधिकारों का क्या होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि क्या यह सही होगा कि आपके अपराध के पीड़ित अलग-अलग जगहों से सिर्फ आरोपित की सुविधा के लिए एक ही जगह आएं।

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि धोखाधड़ी, ठगी और साजिश का हर अपराध अलग और स्वतंत्र मामला है। ऐसे मामलों में पीड़ितों को क्यों परेशान होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि मामलों में पीड़ितों को केंद्र में रखकर विचार करने की जरुरत है।

दरअसल, आरोपितों के खिलाफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र , गोवा और आंध्रप्रदेश में कई आपराधिक मामले चल रहे हैं।

निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होंगे एसएमसी दिशा निर्देश: शिक्षा मंत्रालय

स्वतंत्र चेतना

नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशानिर्देश 2026 को लेकर समाज के कुछ वर्गों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर गुरुवार को स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि ये दिशानिर्देश शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम की धारा 2(एन)(4) के तहत आने वाले निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होंगे, बशर्ते ऐसे संस्थानों को अपने खर्चों के लिए केंद्र, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय से किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न हो।मंत्रालय ने हालांकि कहा कि ऐसे निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागितापूर्ण प्रशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें स्कूलों, अभिभावकों और समुदाय की भी समान भागीदारी होती है। मंत्रालय के अनुसार, अभिभावकों, स्कूलों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करना स्कूलों के समग्र संचालन को बेहतर बनाने और बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार के लिए आवश्यक है।मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एसएमसी दिशानिर्देशों का उद्देश्य स्कूल प्रशासन में अधिक भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

उल्लेखनीय है कि विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय संचालन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। इसके प्रमुख कार्यों में विद्यालय के समग्र कार्यों की निगरानी और शैक्षणिक योजनाओं जैसे समग्र शिक्षा योजना, पीएम श्री और पीएम पोषण के समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन की देख-रेख शामिल हैं।केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 मई को विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। नए निदेर्शों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब एसएमसी केवल प्राथमिक स्तर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कक्षा 12 तक के माध्यमिक विद्यालयों में भी लागू की जाएगी। इसके साथ ही विद्यालय प्रबंधन विकास समिति (एसएमडीसी) की जगह एसएमसी को लागू करने का प्रावधान किया गया है।

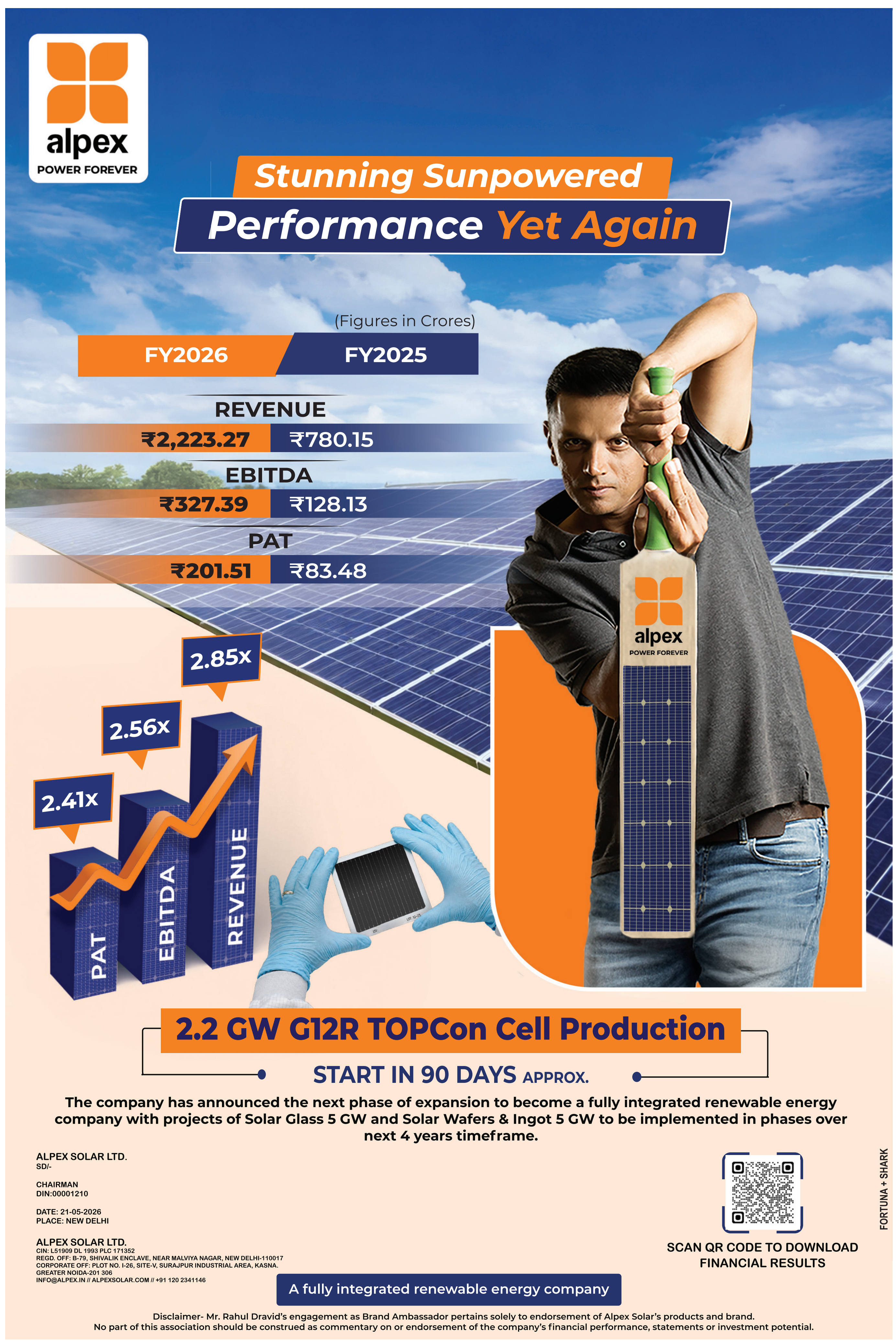

SMART INVESTING
Cigarette may Keep Singeing ITC Books

TO THE RESCUE Heavy dollar sales by state-run banks and expectations of a rate hike helped rupee rebound, but elevated oil prices and FPI outflows continue to weigh

Rupee Moves Up after 10 Days on Likely RBI Intervention

Our Bureau

Mumbai: The Indian rupee, under the cosh for 10 straight days, Thursday rebounded against the dollar in the spot market to log its steepest gains in a fortnight after what dealers described as unusually heavy central bank interventions to support the currency.

Talk that policymakers might even raise interest rates buttressed the rupee, which outshone peers in the continent to emerge as the strongest Asian performer against the dollar Thursday.

The local unit closed at 96.20 per dollar in the Mumbai spot market against the previous close of 96.82. Traders reported heavy dollar sales by state-run banks, likely on behalf of the Reserve Bank of India (RBI), a day after forward market rates for the rupee had breached the psychologically important 100 per USD mark.

"The RBI must have sold $4-5 billion today (Thursday), so there was heavy dollar selling after a long time. The stronger levels offered importers a good opportunity to buy, but I suspect importers hedged only their short-term liabilities," said Anil Bhansali, head of treasury, Finrex Treasury Advisors. "Many are waiting for better levels on expectations the RBI would come up with some measures to protect the rupee."

Intervention was seen even before domestic markets started trading, with the rupee strengthening from around 96.75 a dollar at 8.45 am to open at 96.30. Traders said interventions continued through the day, as the currency moved in a 95.99 - 96.50 range, while stronger rupee levels prompted importers to step in and buy dollars.

"After touching almost 97, the currency recovered today (Thursday). Plus, there were reports that there is a possibility of rate action, which aided the rupee," said VRC Reddy, head of treasury, Karur Vysya Bank. "But underlying sentiments like higher oil prices and FPI outflows continue, and until those persist, there will be weakness."

India is considering all available options, including an interest rate increase, to help stabilise the currency, Bloomberg News reported Thursday.

Reddy said he also expects the depreciation pressure to moderate going forward, as "one positive news item will pave the way for a sharp appreciation in the currency."

DBS Bank, meanwhile, expects the rupee to be in the 95-100 range for the rest of 2026, the institution said in a note Thursday.

Brent crude futures gained $1.39 to $106.4 a barrel on Thursday, according to Reuters. The rupee has depreciated more than 3% in FY27 so far, and had lost nearly 11% in FY26 against the dollar.

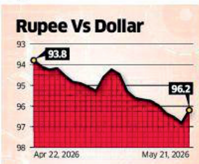

AMID STRONGER EMERGING MARKET ALTERNATIVES...

Foreign Investors Continue to Pull Out from Financials

Sector accounts for nearly 47% of outflows in the first-half of May

Ruchita Sonawane

Mumbai: Foreign investors continued to pare exposure to financials in the first half of May, pulling out ₹17,960 crore from the sector, nearly 47% of the overall foreign outflows during the period, amid concerns over tighter banking margins and India's lower appeal compared to other emerging markets.

"Banks are facing headwinds from higher bond yields, which could impact treasury income, while implementation of Expected Credit Loss (ECL) norms, requiring higher provisioning, is expected to keep return ratios volatile in the near term," said Pankaj Pandey, head of retail research at ICICI Securities.

Between January and April, overseas investors dumped more than ₹91,000 crore worth of financials, a sector with the highest foreign ownership in India.

The Bank Nifty has fallen nearly 7% over the past month, compared with a 4% decline in the benchmark Nifty.

"The valuations in the banking space remain reasonable, and the foreign outflows in the sector are due to these investors wanting to cut exposure to India as a whole, as they find better bets in the rest of the emerging markets," said Siddarth Bhamre, head of research, Asit C Mehta Intermediates. "They cannot reduce weightage in India without selling banking stocks."

Overall, foreign investors sold shares worth ₹38,443 crore across 19 sectors in the first half of May, according to NSDL data. Oil & gas saw outflows of ₹6,885 crore, while telecom stocks witnessed selling worth ₹2,542 crore, extending the pressure seen in April.

Overseas investors bought shares worth ₹11,395 crore across four sectors, with nearly 60% of the inflows directed in the services sector. "The services sector, which includes Adani Group stocks such as Adani Ports and Adani Enterprises, performed well after resolving issues related to the US Securities and Exchange Commission (SEC)," said Pandey.

Pandey said that the MSCI rebalancing next week could draw some foreign inflows, but that is a one-time event.

Mapping the Money Flow (Fig in ₹cr)

Sector	May 1-15	April 2026	Jan-March
NET OUTFLOW			
Financial Services	-17,960	-30,856	-60,829
Oil, Gas & Consumable Fuels	-6,885	-6,703	312
Telecommunication	-2,542	-4,400	-12,261
Information Technology	-1,643	-4,212	-20,658
Fast Moving Consumer Goods	-1,625	-3,205	-14,867
NET INFLOW			
Services	7,019	-953	-3,055
Capital Goods	2,645	4,339	18,044
Metals & Mining	1,698	1,218	13,999
Diversified	33	8	-30

Source: NSDL

IOB Plans to Raise ₹6k-cr

Kolkata: The board of Indian Overseas Bank on Thursday approved a ₹6,000 crore equity raising plan, while the board of Union Bank of India will meet on May 26 to consider capital raising in Tier-1 or Tier-2 capital, the banks said.
- **Our Bureau**

LISTING DAY BLUES

Sebi Proposes Tweaks to Price Discovery for IPOs, Re-listing

Our Bureau

Mumbai: The Securities and Exchange Board of India (Sebi) has proposed changes to the price discovery process for initial public offerings (IPOs) and re-listed shares on the date of their listing.

The move comes in the wake of concerns being raised by market participants that existing rules have in certain cases resulted in artificially suppressed price discovery for re-listed securities. The regulator has suggested changes to the pre-open call auction process, including a new methodology for determining base prices for re-listed stocks and a more dynamic mechanism for widening price bands.

"Representations have been received by Sebi stating that the dummy price band and the mechanism for base price in case of a re-listed scrips are leading to situations of artificially suppressed price discovery," Sebi said in a consultation paper on Thursday.

"Subsequently, there is persistent buying pressure in the scrips in the normal market leading to continuous hit of the upper circuits and additional surveillance measures as applicable in the respective exchanges," it said.

Presently, the pre-open call auction session for IPOs and re-listed shares are from 9am to 10 am.

FY26 PAT UP 19% TO ₹57,453 CRORE

LIC Profit Rises 23% in March Quarter on All-round Show

Growing premiums, higher investment income help insurer net ₹23,467 cr in Q4

Our Bureau

Mumbai: Life Insurance Corp reported a 23% year-on-year rise in consolidated net profit for the March quarter at ₹23,467 crore, driven by strong premium growth, higher investment income and improved operating performance.

The insurer, also India's biggest institutional investor, cautioned that prolonged geopolitical tensions could weigh on savings flows and economic activity. LIC had reported a net profit of ₹19,039 crore in the year-ago period. The board also recommended a final dividend of ₹10 per share for FY26.

₹5.38L CR
NET PREMIUM INCOME UP 10% IN FY26

₹13,009 CR
FIRST-YEAR PREMIUM INCOME UP 17% IN Q4

For the full year, FY26 LIC posted a profit after tax of ₹57,453 crore, up 19% from ₹48,320 crore in FY25, while net premium income rose 10% to ₹5.38 lakh crore from ₹4.90 lakh crore a year earlier.

LIC expects macroeconomic uncertainty arising from the ongoing West Asia conflict to have some impact across sectors, including life insurance savings, however, it will continue targeting double digit growth in new business premium income.

"It is expected that every sector of the country will be impacted by the ongoing crisis," said R Doraiswamy, MD and CEO, LIC. "Naturally, when people experience some difficulty, savings, and that too savings through life insurance, can certainly have an impact, but we will try our best to continue to move towards our targeted growth rate."

First-year premium income rose 17% year-on-year to ₹13,009 crore in the March quarter, while renewal premium income increased 14% to ₹82,233 crore. Single premium collections climbed 22% to ₹70,119 crore.

Investment income, a key earnings driver for LIC, rose around 17% to ₹1.09 lakh crore during the quarter from ₹93,443 crore a year ago. However, the gains were partly aided by a change in accounting policy implemented in the fourth quarter, which contributed around ₹11,000 crore to growth in investment income. The insurer's solvency ratio improved to 2.35 at the end of FY26 from 2.11 a year ago.

LIC also said it continues to focus on non-participating savings and protection products. Protection business registered a growth rate of nearly 29% during the year, helped partly by customers opting for higher sum assured products.

The share of foreign institutional investor ownership in LIC has risen recently to over 0.3% as of March 31, 2026, from 0.22% at the time of the IPO allotment. Shares of LIC closed flat ₹800.70 when BSE benchmark index fell 0.24%.

GAINS 3.3% TO 24.6% Schemes getting popular in an uncertain market

Diverging Multi-asset Fund Returns Show Right Call is Key

The Fund Leaderboard

TOP MULTI ASSET FUNDS BY ASSETS UNDER MANAGEMENT

Scheme	AUM ₹Crore	Last 1 Year Return	Net Domestic Equity (Incl. REITs)	Net Commodities	InvITs	Foreign Equity	Debt, Arbitrage Others^
ICICI Prudential Multi-Asset	83,547	7.1	65.2	10.3	0.4	0.2	24.0
SBI Multi Asset Allocation	17,666	14.6	48.8	10.4	0.0	0.0	40.8
Nippon India Multi Asset	14,738	16.1	51.0	11.4	0.0	5.2	32.4
Kotak Multi Asset Allocation	13,447	24.6	72.5	12.6	0.0	0.0	14.8
DSP Multi Asset Allocation Fund	9,241	19.9	40.0	17.0	0.8	13.4	28.8
WhiteOak Capital Multi Asset	7,118	12.2	36.6	10.1	7.6	0.4	45.3
UTI Multi Asset Allocation	6,865	6.5	64.9	13.3	0.7	0.0	21.0
Aditya Birla Sun Life Multi Asset	6,530	13.5	70.1	13.2	1.5	0.0	15.2
HDFC Multi-Asset Fund	5,887	4.9	57.1	11.5	0.3	0.0	31.1
Quant Multi Asset Allocation	5,257	19.7	52.2	10.2	0.0	0.0	37.6

Source: ValueMetrics Technologies. Asset Allocation Mix as on 30th April 2026. Last one year return as on 19th May 2026.

Prashant Mahesh

Mumbai: For investors who thought simply investing in any multi-asset allocation fund was a sure-shot winning strategy, the past year offered a reality check. Returns from this category, positioned as an all-weather product with allocations spanning equities, debt, precious metals, international equities, REITs and InvITs, ranged from 3.3% to 24.6% in the past year, according to data from ValueMetrics Technologies, reflecting the sharp divergence in performances.

The popularity of multi-asset allocation funds soared in the past year, with the category's assets swelling to ₹1.87 lakh crore from ₹1.13 lakh crore a year earlier, as volatile equities and strong but erratic performances in gold and silver made investors to leave asset allocation to fund managers. These funds are mandated to allocate a minimum of 10% to equity, fixed income and precious metals, but the sharp divergence in returns shows that performance hinges less on the category itself and more on whether money managers got their asset allocation calls right. Those with a higher allocation to gold and silver emerged on top. Kotak Multi Asset Allocation, Quant Multi Asset Allocation, DSP Multi Assset Allocation, HSBC Multi Asset Allocation and Bandhan Multi Asset Allocation were among the top performers last year.

In the year ahead, with equity markets expected to test money managers again, their challenge will lie in remaining ahead of the curve. "The ability to tactically switch between asset classes, actively manage duration, and selectively position within equities across market caps and sectors will remain important," says R Sivakumar, chief investment officer, Axis Mutual Fund.

For instance, Sivakumar believes that while large caps are turning relatively more attractive from a valuation perspective, earnings growth continues to remain better in segments of mid and small caps, making it critical to make selective bets rather than take a broad-based market view. Equity exposure of the top schemes in the category stood in the range of 36% to 73% of their AUM, while allocations to debt and arbitrage were between 14% and 41%, underscoring the variance in asset allocations across fund houses.